रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 1970 (फाल्गुन 23, 1891)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 1970 (PHALGUNA 23, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 10 फरवरी 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 10th February 1970:—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..	251
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	313
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	17
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	317
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	921
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं ..	1309
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	129
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	307
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	101
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं..	55
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधि-सूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	141
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	41
पूरक संख्या 11—	
7 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट 13 फरवरी 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	243 435

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	251
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	313
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	17
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	317
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including Orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	921
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1309
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	129
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	307
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	101
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	10
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	55
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	41
SUPPLEMENT No. 11—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 7th March 1970	423
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 13th February 1970	435

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence and by the Supreme Court

---

समाज कल्याण विभाग

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 फरवरी 1970

सं० एफ० 13/1/70-एस० डब्ल्यू०-2—भारत सरकार देश में बाल-विकास सेवाओं की उन्नति हेतु अनेक उपाय करती रही है। इसके पूर्व श्री गंगा शरण सिंह की अध्यक्षता में "बच्चों के लिए एक कार्यक्रम" तैयार करने के लिये एक समिति गठित की गई थी जिसमें स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा, समाज-कल्याण, योजना तथा प्रशासन-क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य थे। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बाल-कल्याण हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय नीति पर ज़ोर दिया है, जिसमें स्वैच्छिक एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए देश में प्रत्येक बालक के स्वस्थ-विकास पर समुचित बल दिया गया है। विकास योजनाओं के अन्तर्गत बालकों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण संबंधी सेवाओं पर विभिन्न कार्यक्रमों के बनाते समय बाल-समस्या पर एक योजना की आवश्यकता का अनुभव अधिकाधिक हो रहा है।

2. सरकार ने इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रारूप एवं मसौदा तैयार करने हेतु निम्नांकित समिति गठित करने का निर्णय किया है।

अध्यक्ष

(i) श्री पी० पी० आई० वैद्यनाथन,
अतिरिक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य

(ii) श्री टी० आर० जयरामन,
संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

(iii) श्री एस० एन० राणाडे,
प्रधानाचार्य, सामाजिक कार्य का दिल्ली स्कूल।

(iv) श्री वी० एम० कुलकर्णी,
भूतपूर्व सम्पादक, समाज कल्याण विश्वकोष।

(v) डा० के० बागची,
पोषाहार सलाहकार,
स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नागरिक विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(vi) डा० ए० बी० बोस,
संयुक्त निदेशक,
समाज कल्याण प्रभाग, योजना आयोग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

(vii) श्रीमती श्याम कुमारी खां,
सचिव,
बाल कल्याण भारतीय परिषद्,
नई दिल्ली।

सदस्य-सचिव

(viii) श्री एम० सी० नानावती,
सलाहकार (समाज कल्याण),
समाज कल्याण विभाग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

3. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता समाज कल्याण विभाग के बजट से नियमानुसार दिया जाएगा।

आदेश

आदेश किया जाता है कि समिति के सब सदस्यों, भारत सरकार के सब मंत्रालयों/विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय और योजना आयोग को संकल्प की एक प्रतिलिपि भेजी जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रामदास सोनकर, उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(अर्थ विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1970

सं० 1(30)-एस० ई०/69—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम (1956 का 42वां) की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई 27 जून 1969 की वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2561 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभूतियों के वायदा-कारोबार पर प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसका उद्देश्य प्रतिभूतियों की उस समय चल रही अवांछनीय सट्टेबाजी को रोकना था। तब से लेकर केन्द्रीय सरकार को बहुत-से

अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें से कुछ उक्त प्रतिबन्ध के विरोध में हैं और कुछ इस प्रतिबन्ध को जारी रखने के पक्ष में हैं। इस स्थिति में क्या अपेक्षित है, इस बात का अनुमान लगाने में केन्द्रीय सरकार की सहायता करने के लिए वह सरकार एतद् द्वारा एक समिति नियुक्त करती है, जिसके सदस्य ये होंगे :—

1. श्री जे० जे० अंजारिया — अध्यक्ष
2. श्री सी० पी० मुखर्जी — सदस्य
3. श्री पी० एस० नाडकर्णी — सदस्य
4. श्री पी० डी० कसबेकर — सदस्य

2. समिति के विचारणीय विषय ये हैं :—

(1) देश के आयोजित आर्थिक विकास से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में प्रतिभूतियों के वायदा कारोबार की आवश्यकता का अनुमान लगाना;

(2) यदि प्रतिभूतियों का वायदा कारोबार फिर खोलने के लिए अनुमति दी जानी हो तो ऐसे सुरक्षणात्मक उपाय सुझाना जिनसे इस कारोबार की अवांछनीय बातों से बचा जा सकता हो; और

(3) प्रतिभूति संविधान (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42वां) के उद्देश्यों की प्राप्ति के विचार से अन्य कोई सिफारिशें करना।

3. समिति शीघ्र ही और हर हालत में दो महीने के अन्दर-अन्दर, अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों आदि को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राज-पत्र असाधारण में प्रकाशित किया जाय।

आई० जी० पटेल, विशेष सचिव

सरकारी उद्यम कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1970

सं० 8(20)/69-बी० पी० ई० (जी० एम०)—सरकारी विभागों/कार्यालयों और सरकारी उद्यमों को उपयुक्त परामर्शदायी संगठनों का चुनाव करने में सहायता देने के लिए भारत सरकार तकनीकी, इंजीनियरी और प्रबन्ध सम्बन्धी परामर्शदाताओं की एक नामिका तैयार करने के प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे इनकी सेवाओं को प्राप्त कर सकें। तदनुसार, देश में परामर्शदायी संगठनों की कार्यक्षमता और योग्यताओं का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकन समिति बनाई गई है। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. श्री ए० एन० बनर्जी, अतिरिक्त सचिव तथा महानिदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय

सदस्य

2. श्री जी० डी० पाण्डे
3. श्री जे० एम० श्रीनगेश
4. श्री डी० सी० बैजल
5. श्री एन० एन० वांचू
6. श्री ई० डब्ल्यू० आईजैक्स
7. श्री आर० एन० सेन
8. श्री एन० के० बोस
9. श्री के० एम० जार्ज
10. श्री एन० सी० देव
11. डाक्टर जी० आर० डाल्वी
12. श्री पी० के० बसु, निदेशक, सरकारी उद्यम कार्यालय

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की प्रतिलिपि सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित कर दी जाए।

पी० के० बसु, निदेशक

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1970

सं० 18(1) पी० पी० एण्ड डी०/68—राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद्, जिसको सोसाइटी पंजीयन अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां अधिनियम) के अधीन पंजीबद्ध किया गया है, के नियमों के नियम 3 के अन्तर्गत भारत सरकार में निहित शक्तियों के द्वारा तथा भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं० 18 (2)-प्रोड०/66 दिनांक 19 नवम्बर, 1966 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार, उपर्युक्त नियम के खण्ड (क) के अधीन श्री एन० एन० वांचू को 16 जनवरी, 1970 से आगामी आदेशों तक, भारत सरकार की सेवा से निवृत्त हो जाने पर राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के सरकारी निकाय का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

न० ज० कामत, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1970

सं० 1-11/69-एम० ई० आई०—भूतपूर्व इस्पात, खान तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय के संकल्प सं० 1-2/63-एम० ई० आई० के संदर्भ में जो बाल बियरिंग उद्योग के लिए नामिका का गठित करने के बारे में है तथा भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की बाद की अधिसूचना सं० 1-2/65-एम० ई० आई०, दिनांक 19 जुलाई, 1967 है।

2. यह निश्चय किया गया है कि श्री वी० एस० देशपाण्डे, जिन्होंने अब त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री एम० के० जोशी, निदेशक, प्रीसीजन बियरिंग इण्डिया लि० बम्बई, बाल बियरिंग उद्योग की नामिका के सदस्य होंगे।

रसायन मशीन उद्योग के विकास हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन

दिनांक 3 मार्च 1970

संकल्प

सं० 3-6/70-प्रोज०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1-13/69-प्रोज०, दिनांक 7 अगस्त, 1969 जो रसायन मशीन उद्योग

के विकास हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के बारे में है, में, पैरा 5 के पश्चात् निम्नलिखित निविष्टि की जाएगी :—

"5(ए) अध्यक्ष, यथा आवश्यक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकता है ।'

आदेश

आदेश दिया गया कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आर० वी० सुब्रह्मण्यन्, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य, और परिवार नियोजन, तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय

(निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1970

संकल्प

सं० 44/3/69-पी०-2—स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर-विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर-विकास विभाग) के दिनांक 14 मई 1969 के संकल्प संख्या 44/3/69-पी०-2 द्वारा गठित की गई विभागीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को भारत सरकार ने 31 मार्च 1970 तक बढ़ा दिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्रतिलिपि श्री पी० के० सेन, मुख्य नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री को, उनके दिनांक 29 जनवरी, 1970 के पत्र संख्या 30-1-69 एम० एण्ड आई० के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है ।

पी० प्रभाकर राव, संयुक्त सचिव

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय,

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1970

संकल्प

सं० 4-15/68-भूमि—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 6-6/67-जनरल-ii, दिनांक 27 जुलाई 1967, संकल्प संख्या 4-15/68-भूमि, दिनांक 5 मार्च 1968; 24 जुलाई 1968; 28 नवम्बर 1968; 15 मार्च 1969; 5 जून 1969; 5 सितम्बर 1969, 6 दिसम्बर 1969 तथा 9 फरवरी 1970 द्वारा भारत सरकार ने जो भूमि अर्जन पुनर्विचार समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के समस्त ढांचे को शीघ्रता से विकसित होने वाली अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में परीक्षा करने हेतु नियुक्त की थी, उसे अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी तक प्रस्तुत करनी थी । अब भारत सरकार ने उस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को 31 मार्च 1970 तक बढ़ा देने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा भूमि अर्जन समिति के सदस्यों को, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों, विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्र के राजस्व सचिवों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद पुस्तकालय को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

बलबीर बोहरा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1970

संकल्प

सं० 6-31/69 अर्थ नीति—भारत सरकार ने खाद्य और कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 6-2/65-सी० (ई), दिनांक 8 जनवरी 1965 द्वारा स्थापित किए गए कृषि मूल्य आयोग की अवधि को 28 फरवरी 1971 तक आगे बढ़ाने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा विभागों, समस्त राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों, योजना आयोग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के समस्त संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों, अर्थ शास्त्रियों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि प्रशासन से संबंधित विशेषज्ञों के पैनलों के समस्त सदस्यों को भेजी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को प्रकाशित किया जाए ।

भ० रा० पटेल, सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1970

सं० एफ० 14-47/69 यू०—पुनर्वास मंत्रालय की अधिसूचना सं० आर० एच० ए० ई-5(12)/53, दिनांक 21 मई 1955 द्वारा यथा संशोधित पुनर्वास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या आर० एच० ई०/II(5)/52, दिनांक 5 सितम्बर 1952 की दूसरी अनुसूची के पैराग्राफ 7 के साथ पढ़े जाने वाले

पैराग्राफ 6 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री राम स्वरूप चिटकारा, उप शिक्षा सलाहकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, को 21 सितम्बर 1969 से तीन वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में देशबन्धु कालेज, कालकाजी के प्रशासन बोर्ड में पुनः नामजद करती है ।

हरभगवान दास गुलाटी, सहायक शिक्षा सलाहकार

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi-1, the 11th February 1970

RESOLUTION

No. F. 13-1/70-*SW*-2.—The Government of India have been taking various measures to promote welfare services for children in the country. Earlier it had constituted a Committee to prepare "A Programme for Children" under the Chairmanship of Shri Ganga Sharan Sinha, M.P. and with experts in the fields of Health, Nutrition, Education, Social Welfare, Planning and Administration as members. The Committee in its report has emphasised the need of having a comprehensive national policy on child welfare, taking a unified view of the services provided by voluntary and governmental organisations and the additional services necessary and indicating the priority of attention required to be given to ensure the healthy growth of every child in the country. The need for preparing the Childrens' Policy Resolution is increasingly being felt while deciding on different programmes of services, including nutrition, health, education and welfare, for children under development plans.

2. The Government have decided to set up a Committee for the drafting of a Policy Resolution on Childrens' Services.

3. The Committee will consist of

Chairman

(i) Shri P. P. I. Vaidyanathan,
Additional Secretary,
Department of Social Welfare
Govt. of India, New Delhi.

Members

(ii) Shri T. I. Jayaraman,
Joint Secretary,
Ministry of Education
Govt. of India, New Delhi.

(iii) Shri S. N. Ranade,
Principal,
Delhi School of Social Work
Delhi.

(iv) Shri V. M. Kulkarni
Former Editor,
Encyclopaedia on Social Welfare
New Delhi.

(v) Dr. K. Bagchi,
Adviser, Nutrition,
Ministry of Health, Family Planning
and Urban Development
Govt. of India, New Delhi.

(vi) Dr. A. B. Bose,
Joint Director,
Social Welfare Division,
Planning Commission
Govt. of India, New Delhi.

(vii) Shrimati Shyam Kumari Khan,
Secretary, Indian Council for
Child Welfare, New Delhi.

Member-Secretary

(viii) Shri M. C. Nanavatty,
Adviser, Social Welfare
Department of Social Welfare
Govt. of India, New Delhi.

4. The non-official members of the Committee will be given T.A. and D.A. as provided under rules from the budget of the Department of Social Welfare.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Members of the Committee; all the Ministries/Department of the Government of India; Prime Minister's Sectt. and the Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. D. SONKER, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

New Delhi, the 20th January 1970

RESOLUTION

No. 8(20)/69-*BPE*(*GM*).—Government of India have been considering for some time the question of empaneling technological, engineering and management Consultants so as to assist Government Departments/Offices and the public enterprises in the selection of suitable consultancy organisations, whose services they may like to indent on when required. Accordingly, an Evaluation Committee has been set up to assess the capacities and capabilities of consultancy organisations in the country. The Committee will consist of the following :—

Chairman

1. Shri A. N. Banerji, Additional Secretary and Director General, B.P.E.

Members

2. Shri G. D. Pande.
3. Shri J. M. Shrinagesh.
4. Shri D. C. Baijal.
5. Shri N. N. Wanchoo.
6. Shri E. W. Isaacs.
7. Shri R. N. Sen.
8. Shri N. K. Bose.
9. Shri K. M. George.
10. Shri N. C. Deb.
11. Dr. G. R. Dalvi.

Member-Secretary

12. Shri P. K. Basu, Director,
Bureau of Public Enterprises.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. K. BASU, Director,
Bureau of Public Enterprises

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT INTERNAL TRADE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 23rd February 1970

RESOLUTION

No. 20-4/70-*HEM*.—Reference this Ministry's Resolution No. 28-2/66-HECHE, dated the 28th March, 1967 constituting a Committee to review the activities of and to advise on the research and development programme, of the Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal.

2. As Shri K. S. Rangamurti, Director, has since relinquished the charge of post in this Ministry, he has ceased to be the Secretary of the said Committee.

3. Miss M. Seth, Deputy Secretary, in this Ministry is nominated as Secretary of the said Committee with immediate effect in place of Shri K. S. Rangamurti.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

New Delhi, the 28th February 1970

No. 18(1)-*PP&D*/68.—By virtue of the powers vested in the Government of India under Rule 3 of the Rules of the National Productivity Council, which has been registered as Society under the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860) and in partial modification of the late Ministry of Industry Notification No. 18(2)-Prod/66, dated the 19th November, 1966, the Government of India have been pleased under clause (a) of the said Rule to continue Shri N. N. Wanchoo as Chairman of the Governing Body of the National Productivity Council, New Delhi, consequent on his retirement from Government service with effect from the 16th January, 1970, until further orders.

N. J. KAMATH, Jt. Secy.

New Delhi the 28th February 1970

No. 1-11/69-*MLI*.—Reference the erstwhile Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated 25-3-1964 constituting a Panel for the Ball Bearing Industry and the erstwhile Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) subsequent Notification bearing No. 1-2/65-MEI dated 19-7-67.

2. It has been decided that Shri M. K. Joshi, Director, Precision Bearings India Ltd., Bombay shall be Member of the Panel for Ball Bearing Industry *vice* Shri V. S. Deshpande, since resigned.

R. SUBRAMANIAN, Under Secy.

New Delhi, the 2nd March 1970

RESOLUTION

Constitution of an Expert Committee for Development of Chemical Machinery Industries

No. 3-6/70-*PROJ*.—In this Ministry's Resolution No. 1-13/69-Proj dated the 7th August, 1969, relating to the constitution of an Expert Committee for Development of Chemical Machinery Industries, the following shall be inserted after para 5 :—

"5(A). The Chairman may co-opt other members as and when necessary."

R. V. SUBRAHMANIAN, Jt. Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of resolution be published in the Gazette of India.

R. SUBRAMANIAN, Under Secy.

(Department of Company Affairs)

Company Law Board

New Delhi-1, *the 25th February* 1970

ORDER

No. 53(1)/70-*CL.II*.—In pursuance of Sub-clause (ii) of Clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises the undermentioned officers of the Government of India, in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Company Affairs) for the purposes of the said Section 209 :

1. Shri C. R. Mehta, Dy. Director, Inspection, Kanpur.

2. Shri M. L. Sah, Inspecting Officer, Kanpur.

The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of S/Shri C. R. Mehta and M. L. Sah in the Ministry of Finance Department of Company Affairs and Insurance Order No. 51/1/65-CL.II dated the 14th December, 1965.

H. D. PANJWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING & URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 4th December 1969

F. No. 2-4/68-*Dev*(*AP*).—Under Clause 5(v) of the Agreement signed by the Ministry of External Affairs with the Netherlands Foundation for the setting up of a child-care project in Andhra Pradesh, the Government of India, Ministry of Health and Family Planning, Works, Housing and Urban Development (Department of Family Planning) have constituted an Indian Advisory Board to advise on policy and technical matters related to the Project. The Constitution of the Board will be as under :—

Chairman

1. Dr. C. D. Deshmukh.

Members

2. Mrs. Durga Bai Deshmukh,
President,
Andhra Mahila Sabha.
3. Dr. Radha Raman,
Chairman,
Indian Council of Child Welfare.
4. Mrs. Prem Lata Gupta,
Social Worker,
Hyderabad.
5. Commissioner
Deputy Commissioner,
Deptt. of Family Planning,
New Delhi.
6. Dr. C. Gopalan,
Director,
Nutritional Research
Laboratory, Hyderabad.
7. Shri B. P. R. Vittal,
Secretary, Planning & Panchayati Raj,
Government of Andhra Pradesh.
8. Shri Ramamurthy,
Secretary, Deptt. of Education,
Govt. of Andhra Pradesh.
9. Shri N. C. Nanavati,
Advisor, Social Welfare, Govt. of India.
10. Shri I. J. Naidu,
Commissioner, Panchayati Raj,
Govt. of Andhra Pradesh.
11. Shri N. Bhagvan Das,
Secretary, Health, Housing and
Municipal Admn., Govt. of A.P.

The State Government of Andhra Pradesh will designate the officer who would act as the Secretary for this Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to the Government of Andhra Pradesh and that the Notification be published in the Gazette of India for information.

SMT. PREMA JOHARI, Director,
Aided Programmes

(Department of Works, Housing and Urban Development)

New Delhi, the 20th February 1970

RESOLUTION

No. 44/3/69-*P.II*.—The Government of India are pleased to extend, till the 31st March, 1970, the period for submission of the report of the Departmental Committee, set up under the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) Resolution No. 44/3/69-P.II, dated the 14th May, 1969.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India

P. PRABHAKAR RAO, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT & COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 24th February 1970

RESOLUTION

No. 1-2/69-*M(Coord)*.—In the context of slackness in the production and consumption of Chemical Fertilisers and repercussion thereof on the import programme of the commodity, a continuous review of the progress on these aspects is considered necessary. With a view to reviewing periodically the domestic production, consumption and quantities of import necessary of chemical fertilisers, the Government of India in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation have decided to set up a Standing Committee consisting of representatives of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation, Petroleum & Chemicals, Mines & Metals, Iron & Steel and Finance and the Planning Commission.

2. The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

(i) Shri B. R. Patel,
Secretary, Government of India,
Department of Agriculture.

Convenor

(ii) Shri S. M. H. Burney,
Joint Secretary,
Ministry of Food, Agriculture, Community Dev. & Cooperation.

(iii) Shri M. Ramakrishnayya,
Joint Secretary,
Ministry of Petroleum & Chemicals.

(iv) Shri A. T. Bambawale,
Joint Secretary,
Ministry of Finance.

(v) Shri S. S. Puri,
Joint Secretary, Planning Commission.

(vi) Shri G. Ramanathan,
Joint Secretary,
Department of Mines & Metals.

(vii) Shri P. Sabanayagam,
Joint Secretary,
Department of Iron & Steel.

(viii) Shri M. Subramanyam,
Joint Secretary,
Department of Co-operation.

(ix) Shri B. N. Maheshwari,
Joint Secretary,
Ministry of Finance.

3. The terms of reference will be as follows :—

(i) To assess from time to time the actual production of various types of fertilisers and to make future projections on a realistic basis.

(ii) To consider periodically the causes of low production of chemical fertiliser by indigenous units and suggest measures for augmenting the production up to the maximum capacity.

(iii) To review periodically the trends of consumption of fertilisers in the country.

(iv) To assess quantities of fertilisers to be imported.

4. The Committee will meet as often as is considered necessary and may visit such other places as it deems fit for performing its functions. It will evolve its own procedure of work.

RESOLVED that the Resolution may be published in the Gazette of India.

B. R. PATEL, Secy.

New Delhi, the 27th February 1970

RESOLUTION

No. 6-31/69-*Econ.Py.*—Government of India have decided to further extend the life of the Agricultural Prices Commission set up under the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 6-2/65-CE(E) dated the 8th January, 1965, up to the 28th February, 1971.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India, all the State Governments and Union Territories, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Union Public Service Commission, all Attached and Subordinate Offices under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation, all members of the Panel of Economists, Panel of Agricultural Scientists and Panel of Experts on Agricultural Administration.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

B. R. PATEL, Secy.

New Delhi, the 28th February 1970

RESOLUTION

No. 4-15/68-*Lands.*—The Land Acquisition Review Committee appointed by the Government of India *vide* Resolution No. 6-6/67-Genl.II dated the 27th July, 1967 read with Resolution No. 4-15/68-Lands dated the 5th March, 1968, 24th July, 1968, 28th November, 1968, 15th March, 1969, 5th June, 1969, 15th September, 1969, 6th December, 1969 and 9th February, 1970, of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), for examining the entire framework of the Land Acquisition Act, 1894 in the context of a rapidly developing economy, was required to submit its report by 28th February, 1970. The Government of India has since decided to extend the date for submission of the report by the Committee up to 31st March, 1970.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and Members of the Land Acquisition Review Committee, All Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Revenue Secretaries to the State Governments/Union Territories, the Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat and Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. B. VOHRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & YOUTH SERVICES

New Delhi, the 26th February 1970

No. F. 14-47/69.*U.1.*—In pursuance of the provisions contained in paragraph 6 read with paragraph 7 of the Second Schedule to the Notification of the Government of India in the Ministry of Rehabilitation No. RHE/11(5)/52 dated 5th September 1952, as amended by the Ministry of Rehabilitation Notification No. RHAE-5(12)/53 dated 21st May 1955, the Central Government hereby re-nominates Shri R. S. Chitkara, Deputy Educational Adviser, Ministry of Education & Youth Services, as a representative of the Ministry of Education & Youth Services on the Board of Administration of Deshbandhu College, Kalkaji, for a term of three years with effect from the 21st September, 1969.

H. D. GULATI, Asstt. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970